Bengal have approached Central Government to write off the debts for the Damodar Valley Projects;

(b) whether any decision has since been arrived at; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri S. K. Patil): (a) Government have received from the Government of West Bengal a request for a comparative amendment of the Damodar Valley Corporation Act which includes *inter-alia* a proposal to amend Section 30 of the Act so as to treat the money so far spent on the various projects of the Corporation which has been provided as loan by the Government of India to the States of West Bengal and Bihar as money spent by the Corporation on behalf of the Government of India. It has also been proposed that all costs, charges and expenses on projects in future together with work in connection with or incidental to the same, shall be borne by the Government of India. Government have not received any such proposal from the Government of Bihar.

(b) No, Sir. The proposal of the Government of West Bengal is being examined in consultation with the Government of Bihar.

(c) Does not arise.

बम्बई के प्रिन्सेज और विक्टोरिया गोदियों में ट्रान्जिटशेड

७१२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में प्रिन्सेज और विक्टोरिया गोदियों में ट्रान्जिट शेड बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) शेड बन जाने के बाद इन गोदियों की क्षमता कितनी बढ़ जायेगी ; और

(ग) इन शेडों को बनाने पर संभवत: कुल कितना खर्च किया जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). पूरी स्थिति पर प्रकाश डालने वाला विवरण साथ में लगा दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]

बन्दरगाह के मजदूरों के लिये मकान

७१३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में बन्दरगाह के मजदूरों के लिये कितने मकान बनाये जा चुके हैं ;

(ख) ये मकान किस किस श्रेणी के हैं और उन पर कितना खर्च किया गया है; और

(ग) ये मकान मजदूरों को किन शर्तों पर रहने के लिये दिये जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अब तक ३०५४ मकान बनाये जा चुके हैं (ये मकान केवल निरीक्षकों और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिये बनाये गये हैं)

(ख) मकानों की श्रेणियां :—

श्रेणी	संख्या
१. एक कमरे वाले मकान	२,०००
२. दो कमरे वाले मकान	५०२
३. मकान जिनमें दो कमरे, एक रसोईघर, एक शौचालय और एक स्नानागार है ।	५४४
४. शयनागार (जिसमें ८०० आदमी रह सकते हैं) ।	

इन मामलो पर अनुमानत: कुल खर्चा १,४२,३१,५०८ रुपये का हो चुका है। ९६ मकान और बनाये जा रहे हैं।

(ग) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अधिनियम २२ के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत नियमो के अनुसार मकान दिये जाते है। साथ ही इन नियमो मे यह भी निहित है कि जिस व्यक्ति के नाम मकान हो उसकी तनख्वाह मे से उच्चस्तरीय अथवा निर्धारित या रियायती दर के अनुसार (जैसी भी स्थिति हो) और जो कम से कम हो, मकान का किराया १० फी सदी काट लिया जायेगा।

बम्बई बन्दरगाह का विकास

७१४ **श्री म० ला० द्विवेदी** क्या परिवहन तथा संचार मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बम्बई बन्दरगाह के विकास की योजनाए कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री राज बहादुर) इन योजनाओ की प्रगति पर प्रकाश डालने वाला विवरण साथ मे लगा दिया गया है। [देखिय परिशिष्ट ३ अनुबध सख्या ७७]

गांधीधाम का निर्माण

७१५ **श्री म० ला० द्विवेदी :**
सेठ अचल सिह :

क्या परिवहन तथा सचार मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि .

(क) गाधीधाम के निर्माण म अब तक क्या प्रगति हुई है ,

(ख) वहा पानी की क्या व्यवस्था की गई है और उस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) सरकारी इमारतो के निर्माण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इस पर कितना खर्च हो चुका है ?

परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) . (क) गाधीधाम नगर-निर्माण की मास्टर प्लान मे, जो मैसर्ज एडम्स, हावर्ड एण्ड ग्रीले नगर योजना सलाहकार की एक अमेरिकन फर्म द्वारा तैयार की गई है —गाधीधाम नगर-निर्माण की दो व्यवस्थाए है। प्रथम व्यवस्था मे ४३३७ एकड का क्षेत्र शामिल है। इस मे से ५५० एकड मे अदीपुर और बन्दरगाह तथा रेलवे बस्तियो को पूरी तौर पर विकसित कर दिया गया है और ६२१ एकड भूमि को जिसमे सरदार गज और सरकारी भाग के कुछ क्षेत्र शामिल है, आशिक रूप मे विकसित किया गया है।

(ख) ५४ लाख रुपये लागत की इन योजनाओ के कार्यान्वित हो जाने पर प्रति-दिन २० लाख गैलन पानी पहुचाने की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) बन्दरगाह सगठन ने ५४ लाख रुपये की पजी से एक प्रशासनीय कार्यालय, ४७६ कर्मकों के रहने के लिये क्वार्टर, एक अस्पताल के साथ स्वास्थ्य केन्द्र, एक औफिसर क्लब, कर्मचारियो के लिए एक सस्था, एक प्राइमरी पाठशाला और दुकान के साथ आवास-गृह बनाए है।

रेलवे प्रशासन द्वारा जो इमारते बनाई गई है वे ये है—मुख्य गाधी-धाम रेलवे स्टेशन इमारत, रेलवे कार्यालय की इमारत, एक अस्पताल और पदा-धिकारियो तथा कर्मचारियो के लिये ७३५ रहने के मकान। इन इमारतो पर हुए खर्च का हिसाब लगाया जा रहा है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।